भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)

केन्द्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति **10 मार्च, 2022**

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की स्फूर्ति के साथ
23 से 29 मार्च तक साम्राज्यवादविरोधी सप्ताह मनाएं!

दुनिया भर में उफनते साम्राज्यवादविरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि में, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ते हुए फांसी के फंदे पर झूलकर शहीद हुए कॉमरेड्स भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू की शहादत की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष 23 से 29 मार्च तक साम्राज्यवादविरोधी सप्ताह मनाने जा रहे हैं. यह शहादत साम्राज्यवादविरोधी चेतना का एक प्रतीक है. रूसी साम्राज्यवाद ने यूक्रेन पर दुराक्रमणकारी युद्ध छेड़ दिया है. यह युद्ध अमेरिका–ईयू और रूस के बीच भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों में साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है. साम्राज्यवादविरोधी स्फूर्ति के साथ यूक्रेन की जनता इस युद्ध का डटकर मुकाबला कर रही है. उसी तरह इस साल की 29 मार्च फिलिप्पीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीपी) की नयी जन सेना (एनपीए) की 53वीं वर्षगांठ भी है. इस मौके पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी इस मौके पर फिलिप्पीनी कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी नयी जन सेना, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्षरत तमाम उत्पीड़ित जनता एवं राष्ट्रीयताओं का क्रांतिकारी अभिनंदन करती है. उनके संघर्षों की जीत की आकांक्षा व्यक्त करती है. इन संघर्षों के सभी शहीदों को विनम्रतापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करती है. इस संदर्भ में साम्राज्यवाद के विरोध में दोगुने जोश के साथ विविध कार्यक्रम अपनाने दुनिया भर की माओवादी पार्टियों, जन संगठनों, क्रांतिकारी, जनवादी, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का आह्वान करती है.

देश में अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन खत्म होकर भारत को जब झूठी आजादी मिली, जैसाकि पिछड़े देशों में हुआ साम्राज्यवाद भारत में भी नया औपनिवेशिक शेषण लागू किया. 1991 के एलपीजी सुधारों ने साम्राज्यवादी घुसपैठ को और बढ़ावा दिया.

2008 में छिड़ा साम्राज्यवादी आर्थिक व वित्तीय संकट ने समूची दुनिया को हिला कर रख दिया था. इस संकट से बाहर आने के लिए साम्राज्यवाद इसके सारे बोझ को पिछड़े देशों सहित पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग और मध्य वर्ग पर थोप रहा है. हमारे देश में साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ बढ़ते आंदोलनों का दमन करने अर्ध सैनिक बलों की तैनाती और अंधराष्ट्रीयता को उकसाने के लिए ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा का सत्तारूढ़ होना साम्राज्यवाद की जरूरत थी.

भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद शासक वर्गो ने साम्राज्यवादी शोषण की नीतियों को आक्रामक ढंग से अमल किया. अर्ध औपनिवेशिक, अर्धसामंती देश में दलाल नौकरशाही पूंजीपति, बड़े सामंती वर्ग साम्राज्यवाद के साथ मिलीभगत कर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह उनके मातहत बनाए रख रहे हैं. विमुद्रीकरण(डिमॅनिटाइजेशन), जीएसटी, प्राकृतिक संपदाओं व संसाधनों की लूट के कई एमओयू करना, तीन कृषि कानून, मजदूर विरोधी चार श्रम कोड, कश्मीर में धारा–370 व 35ए को रद्द करना, सीएए जैसे क्रूर कानूनों का अमल, समाधान–प्रहार हमलों के जरिए क्रांतिकारी आंदोलन का दमन, देश को धार्मिक आधार पर विभाजित कर 'हिंदू राष्ट्र' की स्थापना की नींव डालना आदि फासीवादी कार्रवाइयां अपनाने लगे हैं.

साम्राज्यवादी पूंजी पोर्ट्फोलियो पूंजी के रूप में हमारे देश में घुसकर देश की सारी पूंजी को लूट रही है. बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रवाहित होकर स्मार्ट् सिटी के नाम पर नगर पालिकाओं व नगर निगमों की नीलामी, सागरमाल के नाम पर बंदरगाह बनाना, देश भर में राजमार्गो का निर्माण, बिजली परियोजनाओं, रेल्वेज आदि में साम्राज्यवादी पूंजी प्रवाहित हो आयी. दूसरी ओर सरकार द्वारा बीमा, बैंकिंग, रेल्वे के निजीकरण, तीन कृषि कानूनों के जरिए जमीनों को साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के हवाले करने की देशद्रोहपूर्ण नीतियां अमल की जा रही हैं.

भाजपा सरकार जिन 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट् अप' जैसी योजनाओं के बारे में चिल्ल पों कर रही है, वो सब देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत नींव पर खड़ा करने के बजाए 'निर्यात प्रेरक वृद्धि', साम्राज्यवादी मूल्य की जंजीर की कड़ियों, साम्राज्यवादी पार राष्ट्रीय कॉरपॉरेट संस्थाओं के लिए स्पेयर पाट्र्स बनाने वाले सप्लायर्स या स्पेयर पाट्र्स की असेंब्लिंग करने वाले संयंत्र बनकर रह जाएंगी, वहीं तक सीमित रहेंगी. इस तरह के उत्पादन से देश साम्राज्यवादियों के नियंत्रण में ही रहेगा.

साम्राज्यवादियों की प्रकृति व पर्यावरण विध्वंस की नीतियों के कारण एवं उनकी युद्ध नीति के तहत वे कोरोना जैसी महामारियों का सृजन कर रहे हैं. इस कोरोना काल में वे आर्थिक क्षेत्रों का पुनरव्यवस्थीकरण कर रहे हैं. इससे असंगठित क्षेत्र, किसान, मध्य वर्ग की जनता तीव्र कठिनाइयों का सामना कर रही है. दुनिया की जनता, हमारे देश की जनता को चिकित्सा के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. वैक्सिन, अन्य दवाइयों की खरीदी के लिए सरकारी खजाना दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों व साम्राज्यवादियों के हवाले किया जा रहा है.

महान शिक्षक लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद का मतलब ही युद्ध है. संकट से उभरने के लिए साम्राज्यवादी युद्ध चाहते हैं. आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक हितों के लिए प्रतिद्वंद्विता के तहत साम्राजयवाद कई युद्धों का कारण बन रहा है. अमेरिका, युरोप (नाटो), रूस, चीन के बीच होड़ तीव्र हो गया है. रूस यूक्रेन पर दुराक्रमणकारी युद्ध कर रहा है. साम्राज्यवादियों पर अपनी सैनिक जरूरतों के लिए आधारित हमारे देश के शासक वर्गों ने न यूक्रेन पर रूस के दुराक्रमण का, ना ही अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की भूमिका का खंडन किया है. हमारे देश के शासक वर्ग क्वाड के

अंतर्गत अमेरिका की सेवा में लगे हैं जिससे समीप भविष्य में हिंद, प्रशांत क्षेत्र में युद्ध ज्वालाएं उठ सकती हैं. साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ करने वाले अंबानी, अदानी जैसे दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ गयी है जबकि 70 प्रतिशत जनता बेहद गरीबी की स्थिति में पहुंच गयी है. इन शोषणकारी नीतियों के खिलाफ देशभर में जनता संघर्ष कर रही है.

देश के किसान दिन–ब–दिन पलायन करने मजबूर हैं या दिहाड़ी मजदूर बन रहे हैं. तीन कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर जारी किसान संघर्ष ने महान जीत हासिल की. मौजूदा 44 श्रम कानूनों की जगह लाए गए चार नए श्रम कोडों के खिलाफ मजदूरों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया. ये नए कोड कई रूपों में मजदूरों के खिलाफ हैं. मजदूरों पर काम का दबाव बढ़ेगा. महिला मजदूरों को रात पाली से कोई छूट नहीं मिलेगी. इस तरह की और भी कई बाते हैं. बैंकिंग, औद्योगिक मजदूर एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी मिलकर निजीकरण के खिलाफ साधारण हड़ताल कर रहे हैं. साम्राज्यवादियों की लूट के अनुकूल भारत के शासक वर्गों द्वारा अपनायी जा रही नीतियों के चलते छात्र, शिक्षक, सभी प्रकार के पेशेवाले, छोटे व्यापारी, लघु एवं मध्यम किस्म के उद्योगों के मालिक जो राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग है, गंभीर परेशानियां झेल रहे हैं. देश की आबादी के करीब 30 प्रतिशत लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने वाले एवं देश की आय का 30 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले लघु एवं मध्यम किस्म के उद्योग इस कदर ध्वस्त हो रहे हैं कि वो फिर से सुधर ही नहीं पाएंगे. महंगाई जैसी जनता के रोजमर्रा की समस्याओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, देश के बड़े पूंजीपतियों की परियोजनाओं के चलते होने वाले विस्थापन के खिलाफ जारी संघर्ष एवं नए पुलिस कैंपों के खिलाफ जारी राज्यसत्ता विरोधी संघर्ष, ये सभी साम्राज्यवादविरोधी संघर्षों का हिस्सा ही हैं. नोटबंदी, जीएसटी एवं दलितों, आदिवासियों, महलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि दमित तबकों पर हुए अत्याचार उन सबों को संघर्ष की राह में ला रहे हैं.

जहां एक ओर देश की जनता की वास्तविक स्थिति इस तरह है, तो दूसरी तरफ सरकार 'आजादी का अमृत महोत्सव' के नाम पर देश की 'आजादी' के 75वें वर्षगांठ 'समारोह' मना रही है. जनता को उनकी वास्तविक समस्याओं से भटकाने के लिए ही यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. 'नया भारत' का कार्यक्रम ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी एजेंडे के अलावा और कुछ नहीं है. यह परिस्थिति व्यवस्था में असली बदलाव की मांग कर रही है. यह बदलाव मूलभूत रूप से होना चाहिए. मजदूर वर्ग के नेतृत्व में चार वर्गों के संयुक्त मोर्चा के जरिए देश में नव जनवादी क्रांति को सफल बनाना होगा. भारत में जारी दीर्घकालीन जनयुद्ध राज्यसत्ता हासिल करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. देश के समस्त उत्पीड़ित वर्गों, तबकों की जनता को साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों, बड़े सामंती वर्गों की शोषणमूलक व्यवस्था को ध्वस्त कर राज्यसत्ता हासिल करने आगे आना होगा.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) की केंद्रीय कमेटी सभी माओवादी पार्टियों, देश एवं दुनिया की तमाम उत्पीड़ित वर्गों, तबकों, राष्ट्रीयताओं की जनता, छात्रों, महिलाओं, युवाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, सभी प्रकार के पेशेवरों, राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का आह्वान करती है कि वे जोश–खरोश के साथ साम्राज्यवादविरोधी सप्ताह मनाएं. इस संदर्भ में रूस द्वारा यूक्रेन पर थोपे गये आक्रमणकारी युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद करें, अमेरिकी साजिश का विरोध करें, नाटो रद्द करने की मांग करें. दुनिया भर में जारी साम्राज्यवादविरोधी, युद्ध विरोधी जन आंदोलनों के प्रति भाईचारा प्रकट करें. दुनिया भर में जारी क्रांतिकारी आंदोलनों, जनयुद्धों, कश्मीर, पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करें. मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों व अन्य तबकों की जनता के संघर्षों के प्रति मजबूत भाईचारा प्रकट करें. विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों, देश के दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के साथ देश की केंद्र, राज्य सरकारों द्वारा किए गए एमओयू रद्द करने की मांग करें. साम्राज्यवाद–दलाल नौकरशाही पूंजीवाद–सामंतवाद विरोधी वर्गसंघर्ष–जनयुद्ध में शामिल होवें! प्रतिक्रांतिकारी रणनीतिक फासीवादी समाधान–प्रहार सैनिक हमलों को परास्त करें!

मार्च 29 – फिलिप्पीन की नयी जन सेना की 53वीं स्थापना वर्षगांठ – के अवसर पर उसकी जय–जयकार करें. फिलिप्पीनी क्रांतिकारी आंदोलन को ऊंचा उठाते हुए 23 से 29 मार्च तक सप्ताह भर समारोहों का आयोजन करें.

उपरोक्त आह्वान को लेकर सभा–सम्मेलनों, रैलियों का आयोजन करें. कॉमरेड्स भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू की शहादत को ऊंचा उठाएं.

अभय

(अभय)
प्रवक्ता,
केन्द्रीय कमेटी,
भाकपा (माओवादी)